



Date : 13 मार्च 2023

क्रिप्टो मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) या क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लाया है।

आभासी डिजिटल संपत्ति



- वित्त विधेयक ने एक नया खंड (47A) दर्ज करके "वर्चुअल डिजिटल एसेट" शब्द को परिभाषित किया।
- प्रस्तावित नए खंड के अनुसार, क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों से उत्पन्न किसी भी जानकारी या कोड या संख्या या टोकन (भारतीय मुद्रा या कोई विदेशी मुद्रा नहीं होने) के लिए एक आभासी डिजिटल संपत्ति प्रस्तावित है।

कराधान के पीछे तर्क

- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने हाल के दिनों में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है और ऐसी डिजिटल एसेट्स में ट्रेडिंग की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।
- इसके अलावा, एक ऐसा बाजार उभर रहा है जहां आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए भुगतान ऐसी दूसरी संपत्ति के माध्यम से किया जा सकता है।
- इन कारकों ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था प्रदान करना अनिवार्य बना दिया है।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स डिजिटल करेंसी से कैसे अलग हैं?

- एक मुद्रा केवल एक मुद्रा है जब यह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है, भले ही यह एक क्रिप्टो हो।

- हालाँकि, जो कुछ भी इससे बाहर है, हम सभी इसे क्रिप्टोकॉरन्सी कहते हैं, लेकिन वे मुद्राएँ नहीं हैं।
- इन्हें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में अपूरणीय टोकन या एनएफटी भी शामिल हैं, जो एक ब्लॉकचैन पर क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति हैं जिसमें अद्वितीय पहचान कोड और मेटाडेटा हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। एनएफटी का उपयोग व्यक्तियों की पहचान, संपत्ति के अधिकार, और बहुत कुछ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी किया जा सकता है।
- यह क्रिप्टोकॉरन्सियों जैसे फंगिबल टोकन से अलग है, जो एक दूसरे के समान हैं और इसलिए, वाणिज्यिक लेनदेन के लिए एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अगले वित्त वर्ष में आरबीआई जो जारी करेगा वह डिजिटल मुद्रा होगी।
- इसे डिजिटल रुपया कहा जाएगा।

धन शोधन निवारण अधिनियम

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002

- मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य उस धन के रूपांतरण या गलत बयानी से है जो अवैध रूप से गैरकानूनी स्रोतों और तरीकों से प्राप्त किया गया है।



- यह भारत में एक आपराधिक अपराध है और इस उदाहरण में आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हैं।
- मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन) के जवाब में पीएमएलए अधिनियमित किया गया था। इसमें शामिल है:
 - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1988
 - बेसल स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, 1989
 - मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की चालीस सिफारिशें, 1990
 - 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और कार्रवाई का वैश्विक कार्यक्रम

- पीएमएलए सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जिसमें व्यक्ति, कंपनियां, फर्म, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों के संघ या निगमन और कोई भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा शामिल है जिसका स्वामित्व या नियंत्रण उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी के पास है।

PMLA में हालिया संशोधन

- अपराध की आय की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण: अपराध की आय में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि किसी अन्य आपराधिक गतिविधि से संबंधित या अनुसूचित अपराध के समान प्राप्त या प्राप्त की गई संपत्ति भी शामिल होगी।
- मनी लॉन्ड्रिंग को फिर से परिभाषित किया गया: मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध नहीं था, बल्कि किसी अन्य अपराध पर निर्भर था, जिसे विधेय अपराध या अनुसूचित अपराध के रूप में जाना जाता है।
- संशोधन मनी लॉन्ड्रिंग को एक अकेला अपराध मानने का प्रयास करता है।
- पीएमएलए की धारा 3 के तहत, उस व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया जाएगा यदि वह किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय में शामिल है।
 - आड़
 - कब्ज़ा
 - अधिग्रहण
 - बेदाग संपत्ति के रूप में उपयोग या प्रोजेक्ट करना
 - बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना
- **अपराध की सतत प्रकृति:** इस संशोधन में आगे उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में तब तक शामिल माना जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों का फल नहीं मिल रहा है क्योंकि यह अपराध एक सतत प्रकृति का है।

इस चरण के प्रमुख बिंदु

ज़रूरत:

- क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में पारदर्शिता की कमी बनी हुई है और इनको चिन्हित करना मुश्किल है।
- यह क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों पर जिम्मेदारी को बढ़ाता है।
- वित्त के डिजिटल युग में, न केवल निवेशकों बल्कि देश के हितों की रक्षा के लिए भी अनुपालन आवश्यक है और इस पहलू में क्रिप्टो उद्योग तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, दुनिया भर की सरकारें और नियामक इस तेजी से विकसित हो रहे स्थान पर करीब से ध्यान दे रहे हैं।
- इस उपाय से जांच एजेंसियों को क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलने की भी उम्मीद है।

मानदंड:

- वीडिए सेवा प्रदाता / व्यवसाय अब पीएमएलए अधिनियम के तहत 'रिपोर्टिंग संस्था' बन गए हैं, और उन्हें अन्य विनियमित संस्थाओं जैसे बैंकों, प्रतिभूति मध्यस्थों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों आदि के समान रिपोर्टिंग मानकों और केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा।

पीएमएलए के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां:

- आभासी डिजिटल संपत्ति (वीडीए) और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान।
- वीडिए के एक या अधिक रूपों के बीच आदान-प्रदान

- वीडिए का स्थानांतरण
- वीडिए या वीडिए पर नियंत्रण को सक्षम करने वाले उपकरणों की सुरक्षा या प्रशासन।
- किसी जारीकर्ता के वीडिए की पेशकश और बिक्री से संबंधित वित्तीय सेवाओं में भागीदारी और प्रावधान।

संबंधित चिंताएं

- अधिसूचना नए मानदंडों का पालन करने के लिए संस्थाओं को समय प्रदान नहीं करती है। क्रिप्टो उद्योग भी चिंतित है कि एक केंद्रीय नियामक की अनुपस्थिति में, क्रिप्टो संस्थाएं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे व्यवहार कर सकती हैं।
- 17 लाख उपयोगकर्ता भारतीय VDA उपयोगकर्ता फरवरी 2022 में केंद्रीय बजट में कर व्यवस्था की घोषणा के बाद से घरेलू केंद्रीकृत VDA एक्सचेंजों से विदेशी समकक्षों पर स्विच कर चुके हैं
- भारतीय क्रिप्टो व्यापारियों ने स्थानीय एक्सचेंजों से अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में 3.8 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की बढ़ोतरी की है।
- इससे कर राजस्व पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, साथ ही लेन-देन का पता लगाने की क्षमता में कमी आएगी – जो मौजूदा नीति संरचना के दो केंद्रीय लक्ष्यों को पराजित करता है।
- वीडिए टैक्स आर्किटेक्चर के नकारात्मक प्रभाव से पूंजी के बहिर्वाह में और तेजी आने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को डराने की संभावना है।

भारत में क्रिप्टो की कानूनी स्थिति

- केंद्रीय बजट 2022-23 में, भले ही सरकार क्रिप्टोकॉरेंसीज के लिए एक टैक्स लेकर आई, लेकिन यह नियमों को बनाने के साथ आगे नहीं बढ़ी।
- इससे पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अलग कर दिया गया था।
- जुलाई 2022 में, RBI की चिंताओं को झंडी दिखाते हुए, वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि किसी भी प्रभावी विनियमन या क्रिप्टोकॉरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए "अंतरराष्ट्रीय सहयोग" की आवश्यकता होगी।
- अप्रैल 2022 से, भारत ने क्रिप्टोकॉरेंसी से हुए लाभ पर 30% आयकर पेश किया।
- जुलाई 2022 में, क्रिप्टोकॉरेंसी पर स्रोत पर 1% कर कटौती के नियम लागू हुए।

आगे का रास्ता/निष्कर्ष

- अगर क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून और दिशानिर्देश हैं, तो निवेशकों को दंडित किए जाने का डर होगा। चीजों को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, भारत में एक्सचेंजों को एक कर वर्ष के भीतर एक निश्चित राशि से अधिक के निवेशकों द्वारा किए गए हस्तांतरण को ट्रैक करना चाहिए और कर अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।
- VDA टैक्स आर्किटेक्चर के प्रभाव को दूर करने के लिए, सरकार को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभ के लिए विभेदित दरों के साथ एक प्रगतिशील कर संरचना अपनानी चाहिए।
- 2022 में वीडिए से संबंधित एक नई कर व्यवस्था की घोषणा की गई, जो उपयोगकर्ताओं को घरेलू से अंतरराष्ट्रीय समकक्षों में बदल रही थी, जिसने पूंजी के बहिर्वाह को आगे बढ़ाया।